राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 217

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 14 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

चार दिन की चांदनी होती है, टेस्ट क्रिकेट नहीं : सहवाग

>> 14

सीएए पर विपक्ष का कुनबा बिखरा

लगा झटका ▶ सोनिया की बैठक से सपा, बसपा, टीएमसी, आप और शिवसेना ने बनाई दूरी

कांग्रेस की अगुआई वाली बैठक में नहीं आने के सबके अपने-अपने कारण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 20 दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेकर सरकार पर मंदी, महंगाई से ध्यान हटाने व देश बांटने का लगाया आरोप
- विपक्ष शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में एनपीआर प्रक्रिया शुरू नहीं कराने की भी अपील

नई दिल्ली में सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद (बाएं से) सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, भाकपा नेता डी. राजा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एएनआइ

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(एनआरसी) और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर(एनपीआर) के खिलाफ अभियान में जुटा विपक्षी दलों का कुनबा बिखरता दिख रहा है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में इस टूट की स्पष्ट झलक दिखी। विपक्ष की साझा लड़ाई से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी (आप) और शिवसेना ने हाथ खींच लिया है।

हालांकि कांग्रेस समेत 20 दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया और सरकार से सीएए वापस लेने तथा एनपीआर की प्रक्रिया रोकने की अपील की। विपक्ष का यह भी कहना है कि मंदी, बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसे विभाजनकारी कदम उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा।

सीएए के खिलाफ अभियान को धार देने के लक्ष्य से सोनिया ने सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो पहले ही बैठक में नहीं आने की घोषणा कर दी थी। सपा ने भी इसी राह पर चलते हुए बैठक से दूरी बना ली। विपक्षी खेमे का नया-नया हिस्सा बनी शिवसेना का किनारा करना भी किसी झटके जैसा रहा। शिवसेना ने कहा कि उसे बैठक का संदेश ही नहीं मिला था। टीडीपी और द्रमुक की अनुपस्थिति ने भी खेमे को हैरान किया। आम आदमी पार्टी का बैठक से दूर रहना बहुत चौंकाने वाला नहीं रहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने बैठक में जाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सपा, बसपा या टीएमसी के प्रतिनिधि भले बैठक में नहीं आए हों मगर सीएए-एनआरसी के खिलाफ हैं और इस पर उनका समर्थन हासिल है। इस बैठक में शरद पवार, सीताराम येचुरी, झारखंड के मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, शरद यादव, राजद के मनोज झा आदि विपक्ष के प्रमुख चेहरे शामिल थे। कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल बैठक में शरीक हुए।

किया जाएगा प्रतिरोध पेज>>5

एनपीआर को सरकार बना रही एनआरसी की बुनियाद : सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा,सीएए-एनआरसी पर प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विरोध करने वालों के खिलाफ सत्ता की ताकत का चाबुक चलाया जा रहा है। सोनिया ने कहा, संविधान की अनदेखी कर जेएनयू, एएमयू, बीएचयू से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। असली मुद्दा आर्थिक गतिविधियों और विकास का धराशायी होना है, जिससे गरीब व आम आदमी जूझ रहा है। मगर मोदी-शाह के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। विपक्षी दल मिलकर सरकार के इस मंसूबे को नाकाम करेंगे। सोनिया ने कहा कि एनआरसी असम में नाकाम साबित हुआ और मोदी-शाह की सरकार अब एनपीआर पर फोकस कर रही है। सरकार के फोकस से साफ है कि वह एनपीआर को एनआरसी की बुनियाद बना रही है।

आइसीआइसीआइ बैंक ने चंदा कोचर से वसूली को किया हाई कोर्ट का रुख

मुंबई, प्रेट्र : आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आइसीआइसीआइ बैंक ने चंदा कोचर की एमडी और सीईओ के पद से बर्खास्तगी को प्रभावी करने तथा वेतन और भत्तों के रूप में उन्हें दी गई रकम की वसूली के लिए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बैंक ने 10 जनवरी को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोचर की तरफ से पूर्व में दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की और कहा कि इस मुद्दे को कामर्शियल याचिका के तौर पर लिया जाना चाहिए। हलफनामे के अनुसार, बैंक ने कोचर से क्लॉबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए याचिका दाखिल की है। क्लॉबैक प्रावधान के तहत गड़बड़ी पाए जाने या लाभ में कमी पर किसी कर्मचारी से इंसेंटिव आधारित वेतन या बोनस को वापस लिया जा सकता है।

जस्टिस आरवी मोरे और एसपी तावडे की पीठ ने सोमवार को कोचर के वकील को बैंक के हलफनामे का अध्ययन कर जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है।

सरोकार

कई शहरों में लगी हैं रेणु की बनाई कलाकृतियां

पठानकोट : साढ़े चार फुट की लड़की बड़ी-बड़ी मूर्तियां कैसे गढ़ेगी..., कभी इस ताने को झेलने वाली पठानकोट की रेणु बाला आज मूर्तिकला में जाना-पहचाना नाम हैं। पिछले दस वर्षों में उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां गढ़ीं, जो विभिन्न शहरों का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

धाकड़ बेटियां! पुरुष वर्चस्व वाले दंगलों में लगा दी है सेंध

बागपत : पहलवानों की धरती बागपत में महिला मल्लों की फौज खड़ी हो रही है। पसीना बहा रही इन लड़कियों को कुश्ती के पारखी भी सलाम ठोंकते हैं। इन्हें ये मान-सम्मान यूं ही नहीं मिल रहा। इनमें कई तो ऐसी धाकड़ हैं, जो पुरुष पहलवानों को भी चुनौती दे देती हैं। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

महिलाओं से भेदभाव पर तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई

नई दिल्ली : महिलाओं के साथ धार्मिक मामलों में भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों और कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल से सुनवाई की रूपरेखा तैयार करने को कहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में दिक्कतें बरकरार

शिमला : हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सोमवार को हुई बारिश व बर्फबारी से परेशानियां बरकरार हैं। पहाड़ों पर मौसम के तीखे तेवरों के चलते दिल्ली-एनसीआर में ठंड और बढ़ गई है। इससे लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

फ्लिपकार्ट, अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट व अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इन कंपनियों पर अनुचित गतिविधियां अपनाने, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने और पसंदीदा विक्रेताओं से गठजोड़ करने जैसे आरोप हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पूर्व तानाशाह मुशर्रफ की मौत की सजा असंवैधानिक करार

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा खारिज करते हुए विशेष अदालत को ही अंवैधानिक करार दे दिया है। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी।

बराबरी का मुकाबला

पहला वनडे
भारत vs ऑस्ट्रेलिया
दोपहर 1:30 बजे से
स्थान : मुंबई
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

आईशी घोष से 40 मिनट में पूछे सौ से ज्यादा सवाल

- जेएनयू हिंसा मामले में छात्र संघ अध्यक्ष समेत तीनों छात्रों से पूछताछ
- पूछताछ के लिए तीनों को दोबारा बुला सकती है एसआइटी

नई दिल्ली में सोमवार को जेएनयू परिसर में साथी छात्रों के साथ छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष। एएनआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत तीन छात्रों से पूछताछ की। आईशी से एसआइटी की महिला पुलिस अधिकारियों ने जेएनयू कम्यूनिटी सेंटर में करीब 40 मिनट तक पूछताछ की। वहीं वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े वाष्कर विजय और पंकज मिश्रा से भी प्रशासनिक भवन स्थित एसआइटी कार्यालय में करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि तीनों से घटना के संबंध में विस्तार से पूछताछ की गई और यह जानने की कोशिश की गई कि घटना के दौरान वे कहां थे। मारपीट व तोड़फोड़ में वह शामिल थे या नहीं। उन्होंने क्या देखा। तीनों से 100 से अधिक सवाल पूछे गए। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, इनसे दोबारा भी पूछताछ की जाएगी। शनिवार को क्राइम ब्रांच ने वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े सात व दक्षिणपंथी छात्र संगठनों से जुड़े दो विद्यार्थियों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था।

जेएनयू में हुई हिंसा के मामले में गत शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने जिन नौ छात्रों के फोटो जारी किए थे, उनमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष,पूर्व छात्र चुनचुन कुमार, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र पंकज मिश्रा, संस्कृत के शोध छात्र योगेंद्र भारद्वाज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर ऐंड कल्चरल स्टडीज के छात्र प्रिया रंजन, स्टडीज ऑफ कोरियन लैंग्वेज के विकास पटेल, स्कूल ऑफ सोशल साइंस-सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज के डोलन समांता, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सुचेता तालुकदार व एमए के छात्र वास्कर विजय शामिल हैं। (पेज-6 भी देखें)

उप्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, लखनऊ-नोएडा से शुरुआत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर, दोनों जिले मेट्रोपोलिटन सिटी घोषित
- पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को मिले 15 नए अधिकार

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एस पांडेय

नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह जागरण

उत्तर प्रदेश में आखिरकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। इसकी शुरुआत लखनऊ और नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में हो गई है। दोनों जिलों को मेट्रोपोलिटन सिटी भी घोषित किया गया है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। एडीजी सुजीत पांडेय लखनऊ और एडीजी आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने 15 प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस को दिए हैं, जो अभी जिला मजिस्ट्रेट के पास थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, फायर, इंटेलीजेंस, कारागार अधिनियम, अनैतिक व्यापार, पुलिसद्रोह अधिनियम अब पुलिस कमिश्नर के पास रहेंगे। पुलिस आयुक्त ही तय करेंगे कि कौन से अधिकार किस स्तर के अधिकारी को दिए जाएं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।

उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू हो रही इस व्यवस्था की छह-छह माह में गहन समीक्षा होगी, जिससे यह तय किया जा सके कि वास्तव में कानून-व्यवस्था में क्या बदलाव व पुलिसिंग में किस तरह के सुधार हुए हैं। नई व्यवस्था के तहत लखनऊ में आइजी स्तर के दो अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त के पदों पर तैनात होंगे। इनमें एक संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था व एक संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध होंगे। एसपी स्तर के 10 अधिकारी पुलिस उपायुक्त होंगे। वहीं नोएडा में डीआइजी स्तर के दो अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त होंगे। इनमें एक संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था व दूसरे संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध होंगे। इसके अलावा एसपी स्तर के सात अधिकारी पुलिस उपायुक्त होंगे।

लखनऊ में अब 40 और गौतमबुद्धनगर में 24 थाने : मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिकों और पुलिस महकमे की दृष्टि से यह बेहद अहम निर्णय है। पुलिस सुधार का सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वर्षों से महसूस किया जा रहा था कि यहां भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो। लखनऊ सिटी में दो नए थानों समेत 40 थानों को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में मान्यता देते हुए कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। नोएडा में भी दो नए थानों फेज-वन व कोतवाली-142 को मंजूरी दी गई है। अब नोएडा में कुल 24 थाने हो जाएंगे।

महिला सुरक्षा का जिम्मा महिला आइपीएस अधिकारी को पेज>>4

राजपथ पर इस बार दिखेगी राफेल के रूप की झलक

नई दिल्ली : वायुसेना को मिलने जा रहा सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल भले अभी कुछ महीनों बाद भारत आएगा मगर इसकी झलक इस बार राजपथ पर दिखाई देगी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और आकाश मिसाइल के साथ राफेल का प्रतिरूप भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होगा। वहीं दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमानों के साथ राजपथ के ऊपर उड़ान भरेंगे। (पेज-6)

डीएसपी देविंदर से छिन सकता है वीरता पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

देविंदर सिंह फाइल फोटो

- पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह सचिव को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह से वीरता पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के दो वरिष्ठ अधिकारी भी डीएसपी और दो आतंकियों से पूछताछ करने श्रीनगर पहुंच गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन जांच का जिम्मा एनआइए को सौंप सकता है।

अफसरों ने बताया कि देविंदर और आतंकियों के रिश्ते की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय व गृह सचिव को सौंप दी गई है। वहीं, आतंकरोधी अभियानों में हिस्सा लेने के लिए समय पूर्व पदोन्नति के आधार पर सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बने देविंदर को 2017 में प्रदान किए गए पुलिस वीरता पुरस्कार को भी वापस लिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

हवाई जहाज से जाने की थी योजना : अफसरों के मुताबिक, देविंदर लंबे समय से आतंकियों से जुड़ा था। उसने आतंकियों को कई बार पुलवामा के त्राल स्थित पैतृक घर और श्रीनगर स्थित आवास पर पनाह दी थी। शनिवार को नवीद व अन्य तीन को कार से चंडीगढ़ रवाना होने से पहले शुक्रवार रात उसने आतंकियों को श्रीनगर स्थित घर में ठहराया था। उसने सभी को प्लेन से ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के डर से इरादा बदल दिया था। उसने आतंकियों को निकालने के लिए चार दिन की छुट्टी भी ली थी।

पुलवामा पुलिस लाइन पर हुए हमले की अहम जानकारी मिली पेज>>6

आम्रपाली मामले में जेपी मॉर्गन की संपत्तियां जब्त करने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बंद हो चुके आम्रपाली ग्रुप के साथ लेनदेन में शामिल रही अमेरिकी कंपनी जेपी मॉर्गन की भारतीय संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। मॉर्गन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) मानकों का उल्लंघन कर गृह खरीदारों का पैसा हड़पने में मदद करने का आरोप है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने ईडी को आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा और दो अन्य निदेशकों शिव प्रिया व अजय कुमार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दे दी, जो पहले से जेल में हैं।

जेपी मॉर्गन व आम्रपाली ग्रुप के बीच हुए शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के मुताबिक, अमेरिकी कंपनी ने 20 अक्टूबर, 2010 को 85 करोड़ रुपये निवेश किए थे। इसके तहत कंपनी के लाभ पर 75 फीसद हक जेपी मॉर्गन का था। बाद में इन शेयरों को दो कंपनियों मेसर्स नीलकंठ और मेसर्स रुद्राक्ष ने 140 करोड़ में जेपी मॉर्गन से खरीद लिया। ये दोनों कंपनियां आम्रपाली के ऑडिटर अनिल मित्तल के चपरासी व कार्यालय सहायक के नाम पर थीं। जेपी मॉर्गन के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने यह पैसा अमेरिका भेज दिया था। इस पर पीठ ने कहा, 'उनकी (जेपी मॉर्गन) भारत में बहुत सारी संपत्तियां हैं। आप उतनी ही रकम के उनके कार्यालय या कारपोरेट संपत्तियां जब्त कर लें। उसके बाद वे दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे और हम इसे देखेंगे।' सिंह ने बताया कि कंपनी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। दो दिसंबर 2019 को ईडी ने कहा था कि उसे मॉर्गन के खिलाफ फेमा उल्लंघन के सुबूत मिले थे और आम्रपाली ग्रुप से लेनदेन के संबंध में कंपनी के भारत प्रमुख के बयान भी दर्ज किए गए थे।

आम्रपाली की संपत्तियों की शीघ्र नीलामी के लिए चार सदस्यीय समिति गठित पेज>>6

हर गांव के पास मजबूत होगा बैंकिंग नेटवर्क

सरकार का एजेंडा

पीएम जनधन योजना के अगले चरण की तैयारी, बजट में घोषणा संभव, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार पर होगा जोर, ग्राहकों को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हर गांव व हर परिवार को बैंकिंग सेवा देने का काम कर चुकी मौजूदा राजग सरकार का अगला एजेंडा ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा को और मजबूत बनाने का है। इसके लिए पीएम जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अगले चरण को लागू करने की तैयारी है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में कर सकती हैं। घोषणा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के अभियान पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए निजी दुकानों, उर्वरक बिक्री केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय सरकारी निकायों की मदद लेने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार की यह घोषणा आरबीआइ की फाइनेंशियल इनक्लूजन पर आगामी पांच वर्षों की राष्ट्रीय रणनीति पर आधारित होगी। बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक जन धन योजना का अगला चरण वर्ष 2024 तक देश के हर बैंक अपने ग्राहक को उसके मोबाइल फोन पर

बैंकिंग सेवा देना सुनिश्चित कराएगा। यह वित्तीय व तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए बहुत ही व्यापक अवसर पैदा करेगा। साथ ही यह मार्च, 2022 तक टीयर-दो से टीयर-छह श्रेणी के सारे शहरों (मछोले से लेकर बेहद छोटे शहरी इलाकों) को लेस-कैश बनाने का भी काम करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत पहले ही बैंक खाते के अलावा कुछ दूसरे वित्तीय व बैंकिंग उत्पाद ग्राहकों को दिए जाने लगे हैं। लेकिन दूसरे चरण में हर व्यस्क ग्राहक को उसकी इच्छा व जरूरत के मुताबिक बैंक खाते के साथ कर्ज लेने की सुविधा, माइक्रो लाइफ व नॉन-लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद भी देने की व्यवस्था होगी। बैंकों व बीमा कंपनियों को कहा जाएगा कि इस उद्देश्य से वे खास किस्म के बीमा उत्पाद तैयार करें। साथ ही वित्तीय साक्षरता का नया अभियान भी बैंकों व वित्तीय कंपनियों के स्तर पर शुरु किया जाएगा और इसकी समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा।

रेलवे में निजी क्षेत्र की एंट्री आसान बनाने का पेश हो सकता है खाका

नई दिल्ली : रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को इस बार के बजट से नया आयाम मिलने की संभावना है। इसके तहत निजी क्षेत्र की मदद से 50 स्टेशनों के आधुनिकरण के अलावा 100 मार्गों पर 150 प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। रेल कारखानो के निगमीकरण की योजना का एलान भी हो सकता है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर फोकस की आशा है। वित्त मंत्री निजी क्षेत्र को सुविधाओं व रियायतों की सौगात दे सकती हैं। संरक्षा के मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब रेलवे का ध्यान यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के साथ घाटा कम करने पर है। (पेज-12)